



राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: 12/पू0वि0वि0/रा0से0यो0/2022-23

दिनांक: 11-01-2023



आदेश

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग उत्तर प्रदेश, शासन के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक संख्या-317/सत्तर- रा0से0यो0को0-2022, लखनऊ, दिनांक 01.11.2022 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-PFMS/FCD/2021, दिनांक 09.03.2022 तथा अवर सचिव भारत सरकार के पत्र संख्या-K-11032/3/2022-NSS, दिनांक 06.10.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक में सी0एन0ए0 बैंक खाता-सब्सिडरी खाता (चालू खाता) (शून्य बैलेंस) धनराशि चेक बुक, ई-ट्राजेक्शन सुविधा सहित खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

वित्तअधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संबंधित सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव माननीय कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0-01, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
6. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
9. मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शासकीय शाखा, 11 संसद मार्ग नई दिल्ली-110001।
10. उच्च शिक्षा लेखा अनुभाग।
11. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक सरायखाजा, जौनपुर।
12. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ।
13. उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उ0प्र0शासन, लखनऊ।
14. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
15. कार्यक्रम समन्वयक रा0से0यो0, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
16. वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एन0एस0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वित्तअधिकारी

8

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग
संख्या-317/सत्तर-रा0से0यो0को0-2022
लखनऊ: दिनांक 01 नवम्बर, 2022
कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. का
दिनांक 02.11.22
पत्रिका पृष्ठ सं. 131
पत्रांक सं. 1137
संख्या 0

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1(18)/PFMS/FCD/2021 दिनांक 09-03-2022 एवं अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06-10-2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के संचालन आदि के लिए नये राज्य सी0एन0ए0 बैंक खाता खोले जाने की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह बैंक खाता "Uttar Pradesh State NSS Cell" के नाम से सी0एन0ए0 बैंक खाता (Product Code:10112141) भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा में खोला जायेगा।
- (2) उक्त खाता (0) धनराशि से चेक बुक सुविधा सहित खोला जायेगा।
- (3) उक्त खाते का संचालन सम्बन्धित विभाग के 02 अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।
- (4) उक्त खाते के संचालन हेतु प्रथम अधिकारी, डॉ0 सुनीता गुप्ता, विशेष कार्यधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग तथा द्वितीय अधिकारी श्री गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, नामित किये जाते हैं।
- (5) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय एवं माध्यमिक मण्डल स्तर पर सब्सिडरी खाता (चालू खाता) (0)धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में खोला जायेगा।
- (6) उक्त खाते से नगद के रूप में भुगतान नहीं किया जायेगा। समस्त भुगतान E-Transaction के माध्यम से किये जायेंगे, ताकि कोई अनधिकृत भुगतान सम्भव न हो सके।

डा० राकेश कुमार मोदक

कार्यक्रम संचालन

सं० एस०एस०

संख्या-317(1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06-10-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल न01, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच0, अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शासकीय शाखा, 11 ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/ वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. उच्च शिक्षा लेखा अनुभाग।
9. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ।
10. कुलसचिव/कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय एवं माध्यमिक मण्डल को सब्सिडरी खाता (चालू खाता) (0) धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में खोले जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. गार्ड-फाईल।

02.11.22

कमलेश्वरी जी/
उपाध्यक्ष जी

04.11.22

(डा० सुधीर एम० बोबडे)
प्रमुख सचिव।

आज्ञा से
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

F. No. K-11032/3/2022-NSS
Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports
Department of Youth Affairs
(NSS Section)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 6th October, 2022

To

The Chief General Manager
State Bank of India
Government Branch
Service & Solution Unit, Corporate Centre
2nd Floor, Main Branch Building
11 Sansad Marg, New Delhi-110001

(Kind Attn:- Shri Jai Shankar Prasad, AGM & RM)

Subject:- Implementation of Central Nodal Account (CNA) system for flow of funds under Central Sector Scheme (CSS) in the MoYAS - reg.

Sir,

I am directed to the refer to the subject cited above and to say that as per the guidelines dated 9th March, 2022 (**copy enclosed**) issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, all eligible Central Sector Schemes will be covered under the revised procedure for Flow of Funds w.e.f. 1st April, 2022. This is a mandatory requirement for release of funds to any implementing agency under the Central Sector Schemes. There are two Models prescribed under the guidelines of Ministry of Finance. **Model-1** is implementation through Treasury Single Account (TSA) for those schemes having annual outlay of Rupees more than 500 crore and implemented without involvement of State Agencies. **Model-2** is implementation through Scheduled Commercial Banks for those Central Sector Schemes having annual outlay of Rupees less than 500 crore or where the schemes are being implemented by the State Government Agencies.

2. It is submitted that as the annual budget outlay of **National Service Scheme (NSS)** is of Rs. 283.50 Cr. under BE 2022-23 which is less than the 500 crore therefore, the NSS comes under **Model-2**. Further, Ministry of Finance has accorded the permission to the National Service Scheme that as per the para 8 of DoE's guidelines dated 9th March, 2022, MoYAS may notify each State NSS Cell as CNA provided that such State NSS Cell are State Government Agencies. As a result of, multiple State level CNAs may be opened under the NSS Scheme.

[Signature]
Raw Kumar Sinha
Under Secretary,
Ministry of Youth Affairs & Sports
Shastri Bhawan, New Delhi

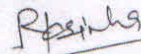
3. The details of funds flow to the States/UTs to conduct the NSS activities is attached herewith for information please.

4. Further, it is stated that the Department of Youth Affairs, National Service Scheme (NSS) has 35 State NSS Cells in the States/UTs to release the NSS Grant to the institutions as mentioned in the para 3 above. Now, as per the Ministry of Finance O.M. dated 9th March, 2022, 35 New CNA bank accounts of State NSS Cell alongwith the Subsidiary Accounts (SAs) at University Level may be opened to flow of funds to the States/UTs. Further, the unspent balance with each of the sub agency in their existing bank Account will have to be transferred to State CNA Account. The Balance lying in State NSS Cells in their existing Bank Accounts will also be transferred to newly opened State CNA Bank Account. Screen Shots of PFMS Portal after mapping and Bank Accounts details (so opened) may be obtained from State CNAs. These Bank details may be mentioned specifically in the Sanction letter. A list of State NSS Cell alongwith their bank account details is also attached for reference.

Further, it is also requested to provide necessary reports and a user-friendly dashboard to officers at various levels to monitor utilization of funds by SAs.

5. In view of the above, you are requested to take necessary action to open 35 CNA bank accounts at State NSS Cells alongwith Subsidiary Accounts (SAs) at University Level with zero balance to smooth flow of funds to the States/UTs as per the directions of Ministry of Finance's O.M. dated 9th March, 2022.

Yours faithfully



(Ravi Kumar Sinha)

Under Secretary to the Government of India
Tel. 011-23386390

Copy to:-

1. The Director (NSS), Directorate of NSS, Shivaji Stadium Annexe, New Delhi.
2. All Regional Director, Directorate of NSS are requested to coordinate with all the SNOs for opening of CNA accounts at State NSS Cell level and their Subsidiary Accounts (SAs) at University level.
3. All State NSS Officers are request to provide the assistance to the SBI for opening the Central Nodal Accounts (CNA) and Subsidiary Accounts (SAs) at University level to flow of funds as per the direction of Ministry of Finance O.M. dated 9th March, 2022.
4. APA, Directorate of NSS, New Delhi to collect the compliance report from the concerned Regional Directors and SNOs for onward submission to this Ministry.

F. No. 1(18)/PFMS/FCD/2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated : 9th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revised procedure for flow of funds under Central Sector Schemes

In supersession of all previous orders issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance regarding release of funds under the Central Sector Schemes, the following procedure shall be followed w.e.f 1st April, 2022 by the Ministries/ Departments of Government of India for flow of funds under the Central Sector Schemes and monitoring utilization of funds released.

Model – 1 : Implementation through Treasury Single Account (TSA)

2. In case of Central Sector Schemes having annual outlay of more than Rs 500 crores and implemented without involvement of State agencies, it shall be mandatory to implement such schemes through the Treasury Single Account (TSA) model. This will ensure that the funds of these schemes are released "Just-In-Time" from the Consolidated Fund of India (CFI) to the beneficiaries/vendors. The Ministries/Departments may opt for Model-1 for other Central Sector Schemes too in consultation with RBI. For the schemes implemented through this model, the following procedure shall be followed by the Ministries/Departments:

- i. For each Central Sector Scheme, the concerned Ministry/Department will designate an Autonomous Body as the Central Nodal Agency (CNA) to implement the scheme.

h. n. a. g. h.

148070/2022/NSS Section

- ii. If there are other agencies involved in implementation of the scheme down the ladder, which get funds from the CNA, these Implementing Agencies (IAs) will be notified as Sub-Agencies (SAs) of the CNA.
- iii. Each CNA will open an account with the Reserve Bank of India (RBI) in e-Kuber. Even in cases where CNA is already registered in the TSA module and has a bank account in e-Kuber for some other grant, it will open separate account in e-Kuber for funds to be provided under each Central Sector Scheme.
- iv. The SAs of every CNA will also open scheme-wise bank accounts with RBI in e-Kuber in line with the requirements of para (iii) above.
- v. The relevant details of all the accounts of the CNA and SAs opened with RBI shall be mapped in the TSA module of PFMS as per the extant guidelines on TSA.
- vi. In respect of funds of Central Sector Schemes, the CNA and SAs shall not open/operate/ park funds in any other bank account except under the provisions made in these guidelines.
- vii. RBI will function as the primary banker to the Ministries/ Departments in this regard without involvement of an agency bank.
- viii. All these accounts in RBI will be "Assignment Accounts". A limit up to which expenditure can be incurred by the CNA/ sub-agencies shall be assigned to these accounts from time to time by the Pay and Accounts Office (PAO) concerned through PFMS.
- ix. Assignment will be based on an expenditure sanction issued by the Programme Division (PD) and the bill preferred by the Drawing and Disbursing Officer (DDO). The e-format of the assignments and Sub-assignments shall have requisite details required for accounting and reconciliation of transactions. The e-Kuber bank account details of the CNA/SAs shall be incorporated in the sanction order.
- x. Consequent upon receipt of the sanction order for release of funds to the CNA alongwith bills from the Drawing and Disbursing Officer (DDO), the concerned

Anurag

- Pay and Accounts Officers (PAOs) shall, through assignments, advise RBI, after exercising all necessary checks, to honour the payment instructions issued by the concerned CNA/SA up to the, "assigned limit" in the advice.
- xi. The PAO shall debit the concerned Head of Account for appropriation but not transfer the cash directly to the CNA. It shall be retained in an interim account in respect of the CNA listed under the parent Ministry/ Department in the public account.
- xii. The assignments shall be uploaded on the TSA module and received electronically by the CNAs as per the existing protocols of TSA module. The CNA may issue e-Sub-assignments in PFMS against this assignment setting limits of expenditure for the SAs.
- xiii. CNAs & SAs shall adhere to all due process while incurring expenditure from the assignment limit sanctioned through PFMS. CNAs shall also ensure that sufficient limit is available in the relevant account before issue of assignment to SAs.
- xiv. The system will be digital and fully online on PFMS with no physical flow of assignments to RBI or expenditure by CNAs/SAs on assignment basis. The electronic file containing a unique sanction ID and necessary details of the sanction order will travel directly from PAO to RBI and concerned CNAs. RBI will maintain individual ledgers in respect of the accounts of the CNAs for watching the availability of assignment.
- xv. PFMS Division in CGA will design requisite reports to enable all Program Division (PDs), Pay & Accounts Officers (PAOs), and other stakeholders to view details of sanction orders, summary and budget balance of assignments/sub-assignments, and expenditure details.
- xvi. Ministries/ Departments administering the schemes concerned should strive to make realistic estimation of Budget under the Central Sector schemes and issue sanction orders according to actual requirements. The savings in the assignments should be anticipated well in advance particularly in the third quarter of



148070/2022/NSS Section

Financial Year and Ministries/Departments shall ensure suitable savings/surrenders are informed to Budget Division during the pre-budget meetings.

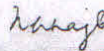
- xvii. Control of limits shall be at the Standard Object Head level.
- xviii. Unutilized assignments will lapse to the Government at the close of the Financial Year as per the extant norms of Budget execution and will not be available to the CNAs /SAs for expenditure in the next financial year. In PFMS too, all e-assignments/e-sub assignments shall cease to exist after the close of financial years and shall be flushed out from the system as per the current practice in TSA module.
- xix. In respect of some transactions like payment of TDS, Income Tax and GST, Opening of Letter of Credit in favour of foreign suppliers, scholarships to foreign students not having account in India, and payment of salaries of the month of March to be paid in 1st week of April, CNAs/SAs may utilize the services of their existing account at commercial banks. They may transfer funds "just in time" to the extent required for meeting such transactions. However, in no case the money transferred under this provision will be parked in a Commercial Bank beyond a period of two weeks.
- xx. Unutilized amount of past releases under the scheme available in the bank account of CNA & SAs shall be deposited in the Consolidated Fund of India.

Model – 2: Implementation through scheduled commercial banks

3. In case of Central Sector Schemes having (a) annual outlay of less than Rs 500 crores or (b) the schemes are being implemented by agencies of the State Governments exclusively or in addition to the central agencies or (c) other schemes not covered in Model-I, the following procedure will be followed by the Ministries/ Departments :

Large

- (i) Every Ministry/ Department will designate a Central Nodal Agency (CNA) for implementing each Central Sector Scheme. The CNA will open a Central Nodal Account for each Central Sector Scheme in a scheduled commercial bank authorized to conduct Government business by the Ministry/ Department concerned.
- (ii) Implementing Agencies (IAs) down the ladder will be designated as Sub-Agencies (SAs). The SAs will use the CNA's accounts with clearly defined drawing limits set for that account. However, depending upon operational requirements, zero balance subsidiary accounts for each scheme may also be opened by the SAs.
- (iii) All zero balance subsidiary accounts will have allocated drawing limits to be decided by the CNA concerned from time to time and will draw on real time basis from the Central Nodal Account of the scheme as and when payments are to be made to beneficiaries, vendors etc. The available drawing limit will get reduced by the extent of utilization.
- (iv) For seamless management of funds, the main account and all zero balance subsidiary accounts should be maintained with the same bank. However, Ministry/ Department may choose different banks for opening Central Nodal Accounts of different Central Sector Schemes.
- (v) Only banks having a robust IT system and adequate branch network should be chosen for opening Central Nodal Account and the zero balance accounts of SAs of each Central Sector Scheme. The bank chosen should have the facility to open the required number of subsidiary zero balance accounts and a robust MIS for handling accounting and reconciliation at each level. The bank should also provide necessary reports and a user-friendly dashboard to officers at various levels to monitor utilization of funds by SAs.
- (vi) The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the SAs who should be able to draw funds on real time basis from the CNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure



- proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts.
- (vii) Ministries/ Departments will release the scheme funds for each Central Sector Scheme to the account of CNA concerned strictly on the basis of requirement, keeping in view the balance funds of the scheme available with the CNA as per PFMS or scheme-specific portals fully integrated with PFMS in consonance with Rule 232(v) and 230(vii) of the General Financial Rules, 2017.
 - (viii) The Ministries/ Departments and the CNAs shall ensure that the interest earned from the funds released is mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India in terms of Rule 230(8) of GFR, 2017. The interest component shall be distinctly reflected in the MIS provided by the banks.
 - (ix) The Ministries/ Departments shall release the funds as far as possible in 'Just-In-Time' manner keeping the float in CNAs account to the minimum possible and shall in no case release more than 25% of the amount earmarked for the scheme in a financial year at a time. Additional funds (not more than 25% at a time) will be released only upon utilization of at least 75% of the funds released earlier and in compliance with the conditions of previous sanction.
 - (x) For administrative convenience and efficiency the Program Division may obtain approval of the competent authority and concurrence of the Financial Advisor for more than 25% at a time. But release of funds shall not exceed 25% in one instalment.
 - (xi) After opening of Central Nodal Account of the scheme and before opening zero balance subsidiary account of SAs or assigning them drawing rights from CNA's account, the SAs at all levels shall return all unspent amounts of the scheme lying in their accounts to the Central Nodal Account of the CNA.
 - (xii) It will be the responsibility of the Ministry/ Department concerned to ensure that the entire unspent amount of the scheme is returned by all the SAs to the Central Nodal Account of the CNA concerned before releasing funds to CNAs.

- (xiii) Ministries/ Departments will ensure that releases under all Central Sector Schemes are made strictly as per the actual requirement on the ground, without resulting in any material float with the implementing agencies at any level.
 - (xiv) Ministry/ Department will register the CNAs and all SAs on PFMS and use the unique PFMS ID assigned to the CNA and SAs for making all payments to them. Bank accounts of the CNAs, SAs, vendors and other organisations receiving funds will also be mapped in PFMS.
 - (xv) Payments will be made from the zero balance subsidiary accounts up to the drawing limit assigned to such accounts from time to time. Transactions in each Subsidiary Account will be settled with the Central Nodal Account daily through the core banking solution (CBS) on the basis of payments made during the day.
 - (xvi) CNAs and SAs will mandatorily use the EAT module of PFMS or integrate their systems with the PFMS to ensure that information on PFMS is updated by each SA at least once every day.
 - (xvii) CNAs will keep all the funds received in the Central Nodal Account only and shall not transfer the funds to any other account or not divert the same to Fixed Deposits/ Flexi-Account/ Multi-Option Deposit Account/ Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) account etc. The funds released to CNA shall not be parked in bank account of any other agency.
 - (xviii) Release of funds by the Ministries/ Departments towards the end of the financial year should be avoided to prevent accumulation of unspent balances with CNAs.
4. UTs without legislature work directly in PFMS and should be given Letter of Authorization (LoA). There is no need for them to open a Central Nodal Account. They will ensure that the funds are released on the basis of LoA to the vendors/ beneficiaries 'Just-In-Time'.
5. Secretaries are requested to, and Financial Advisors of Ministries/ Departments shall, undertake monthly review of strict implementation of these guidelines, opening of

Navaj

accounts in RBI, issue of authorization or release of funds to the CNA, utilization of funds by CNAs and IAs and outputs/ outcomes vis-a-vis the targets of each Central Sector Scheme.

6. Gradually, schemes in Model-2 are expected to move to Model-1 depending on readiness of RBI and Ministries for which necessary orders will be issued separately by the Department of Expenditure.


7. The following categories of Central Sector Schemes will be exempted from following these guidelines and may continue in existing mode:

- (i) Central Sector Schemes being implemented by Ministries/ Departments in Direct Benefit Transfer (DBT) mode or reimbursement mode.
- (ii) Central Sector Schemes involving payment of equity share or extension of loan by the Government to a company.
- (iii) Central Sector Schemes where 100% payments are made by the Ministry/Department directly to the vendors/beneficiaries against the bills/claims raised by the vendors/beneficiaries.
- (iv) Central Sector Schemes where funds are transferred by the Ministry/Department directly to multiple Implementing Agencies (IAs) and amount transferred to any agency does not exceed Rs. 10 lakhs per annum.
- (v) Central Sector Schemes in which funds are transferred to the Indian Missions abroad for implementation of the scheme.
- (vi) Central Sector Schemes being implemented exclusively from a corpus/revolving fund approved by the Cabinet.
- (vii) Central Sector Schemes where expenditure is based on authorization and is incurred on real time basis with no float. However, in such cases Ministry/Department shall avoid the mode of transfer of funds through Civil Deposit and the option of Letter of Authorization should be adopted.



148070/2022/NSS Section

8. In cases where there is no Central Autonomous Body in a Ministry/Department or where the Ministry/Department wishes to implement the scheme directly through State Government agencies, such State Government agency will be designated as CNA. However, there shall not be more than one CNA per State. The funds in such cases will be released by the Ministry/Department to the CNA directly and not through state treasury
9. An illustrative list of roles and responsibilities of CNAs is given in Annexure-I.
10. This issues with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).


 (Abhay Kumar)
 Director
 Tel. No. 24360647

To

1. Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
2. Chief General Manager, Reserve Bank of India, Department of Government and Bank Accounts
3. Controller General of Accounts, Department of Expenditure, INA, New Delhi
4. Financial Advisers of all Ministries/Departments of Government of India
5. Additional CGA (PFMS), O/o CGA with the request to take immediate steps for carrying out necessary change in PFMS and designing requisite reports.
6. Additional CGA (GBA), O/o CGA with the request to take necessary steps to implement model 1 of the Guidelines.
7. All Principal CCAs/CCAs of Ministries/Departments

Copy to:

1. Chief Secretaries of all States/Union Territories
2. Principal Secretary Finance of all States/Union Territories

Copy for information:

1. PSO to Secretary (Expenditure)
2. PSO to Special Secretary (Pers.)
3. Sr. PPS to AS (PFC-II)
4. Sr. PPS to AS (PF-S)



Annexure

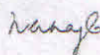
Role and Responsibilities of CNA
Modified Fund Flow Guidelines for Central Sector Schemes

1. Model 1 – Treasury Single Account (TSA) Model

- a. Open Account with RBI in e-Kuber for each scheme under which it receives grant
- b. Mandatorily use TSA Module of PFMS
- c. Map the RBI Account details in TSA Module of PFMS
- d. Receive (electronically in TSA Module) the assignment done by the PAO
- e. Approve the account and scheme mapping of sub-Agencies at Level 1
- f. Issue e-Sub-assignments against the assignment setting limits of expenditure for the sub-Agencies
- g. Ensure funds are not transferred/parked in any other account except as per the guidelines
- h. Process payments by adhering to due process
- i. If existing accounts with commercial banks is to be used for specified purposes in the guidelines (such as payment of TDS, IT and GST, opening of LoC for foreign suppliers etc.), funds shall be transferred just-in-time and, in no case, parked beyond two weeks.
- j. All such unutilized funds (as above) shall be deposited back to the Consolidated Fund of India.

2. Model 2 – through Scheduled Commercial Banks (SCBs)

- a. Open Account with a SCB authorized to do Government business, for each scheme under which it receives grant
- b. Mandatorily use REAT Module of PFMS or integrate own IT system with PFMS for exchange of information (contact PFMS Rollout for details)
- c. Approve the account and scheme mapping of sub-Agencies at Level 1
- d. Approve the scheme mapping of all sub-Agencies using the CNA's Account



- e. Allocate limits for Level 1 sub-Agencies and all other sub-Agencies using the Central Nodal Account
- f. Ensure funds are not transferred/parked in any other account of any Agency
- g. Submit UCs after utilization of the funds that were transferred in the Central Nodal Account
- h. Ensure that interest earned from the funds released is remitted to the Consolidated Fund of India

3. One time activity -

- a. Ensure refund of unspent balance of lower level Agencies to the Central Nodal Account. This is needed after opening of the Central Nodal Account and other Zero Balance Subsidiary Accounts, and prior to assigning the drawing rights to sub-Agencies.

haseeb